(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) और (ग) हथकरघा बुनकरों की मुख्य समस्या सूत के बढ़ते हुए मूल्य हैं न कि सूत का उपलब्ध न होना। इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार ने हथकरघा बुनकरों को सहयोग देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

1. हथकरघा क्षेत्र में अपेक्षित मात्रा में हैंक यार्न की उपलब्धता बनाएं रखने के लिए वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा हैंक यार्न बाध्यता को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। विदेश व्यापार के महा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सूत के निर्यातकों को सूत निर्यात करने से पूर्व हैंक यार्न बाध्यता की शर्तों को पूरा करना होता है।

2. नई कताई मिलों की स्थापना, वर्तमान मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए और साथ ही हथकरघा क्षेत्र में सूत उपलब्ध कराने के लिए मार्जिन मनी देते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण सहायता देने में विस्तार।

3. हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना को 20 मिलियन किलोग्राम सूत की डिलिवरी के लक्ष्य और सब्सिडी की दर 20 रु॰ प्रति किलोग्राम बढ़ाकर वर्ष 1995-96 में जारी रखना।

4. विभिन्न राज्य सरकारों को 20 मिलियन किलोग्राम के बढ़ते हुए लक्ष्य के साथ मिल गेट मूल्यों पर राष्ट्रीय हरकरघा विकास निगम के माध्यम से हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए मिल गेट मूल्य योजना को जारी रखना।

5. समूचे देश में हथकरघा बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य हथकरघा विकास निगमों और राज्य शीर्ष हथकरघा संघों के माध्यम से 100 सूत डिपो और 20 मोबाइल वैन आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

वस्त्र उद्योग के रुग्ण एककों का आधुनिकीकरण

5392. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वस्त्र उद्योग के रुग्ण एककों का आधुनिकीकरण करने के लिये और इस प्रक्रिया में कामगारों को सम्मिलित करके इन एककों में सहयोग का वातावरण पैदा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत वर्षों में इस दिशा में क्या-क्या प्रयास किए गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) से (ग) टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशनों ने 79 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 2005.72 करोड़ रु॰ के निवेश पर एक योजना तैयार की है। आधुनिकीकरण योजना अन्य बातों के साथ-साथ 36 गैर-अर्धक्षम मिलों का 18 अर्धक्षम मिलों में पुनर्संरचना के बारे में परिकल्पना की गई है। एन टी सी पर श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति ने सिफारिश की है कि एन टी सी मिलों के साथ-साथ इसकी अधिग्रहित मिलों को आधुनिकीकरण द्वारा अर्धक्षम बनाया जा सकता है।

वस्त्र उद्योगों पर वस्त्र नीति का प्रभाव

5393. **श्री आस मोहम्मद:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस तथ्य की जांच कर रही है कि वस्त्र नीति का रुग्ण वस्त्र उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार वस्त्र नीति की वर्तमान संरचना के आधार पर वस्त्र नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।